लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

विद्युत भवन–2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना–800 021, दूरभाष : +91–612–250 4980, फैक्स : +91–612–250 4960, वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.in

Ref. NO. : BRLPS/LSBA/ESH/08/16/043 **Dated :** 21.12.2016

SBM-G एवं LSBA के IMIS पर दिनांक 06-07 दिसम्बर, 2016 को पटना में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला का कार्यवाही प्रतिवेदन

1. उपस्थिति – यथा पंजी ।

   राज्य स्तरीय पदाधिकारी – (मिशन निदेशक – LSBA बिहार, राज्य समन्वयक-बिहार, सलाहकार इत्यादि)

   जिला स्तरीय पदाधिकारी – (जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबंधक - जीविका, प्रखंड समन्वयक, प्रखंड परियोजना प्रबंधक-जीविका, डाटा इंट्री ऑपरेटर, कार्यपालक सहायक इत्यादि)

SBM-G IMIS ISSUES AND REMEDIAL MEASURE

2. स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण के IMIS से सम्बंधित मुद्दें (ISSUES) को डॉ. अशोक कुमार (LSBA-MIS) के द्वारा सभी जिलों से चर्चा कर संकलित किया गया और ओम प्रकाश अग्रवाल (PSA-भारत सरकार) के साथ साझा किया गया | बिन्दुवार मुद्दें निम्नवत है –
   - I. राज्य द्वारा जिलों के लक्ष्य संशोधित करने की सुविधा दी जाय |
   - II. प्रखंड स्तर पर SBM-G के IMIS का login id और password की सुविधा दिया जाय |
   - III. राज्य के अनुमोदनोपरांत जिलों को Module B05 में लक्ष्य को बढ़ाने की सुविधा प्रदान की जाय |
   - IV. राज्य के अनुमोदनोपरांत सम्बंधित जिलें अपने अधीनस्थ प्रखंडो के डाटा (BLS Data) को घटाने तथा बढ़ाने की सुविधा प्रदान की जाय |
   - V. Module B02 में लाभार्थियों को Id संख्या से खोजने की सुविधा दी जाय |
   - VI. Module B02 में offline लाभार्थियों के नाम में संशोधन की सुविधा दी जाय |
   - VII. राज्य के अनुमोदनो उपरांत सम्बंधित जिलों द्वारा बेसलाइन सर्वे डाटा को एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड, एक पंचायत से दूसरे पंचायत तथा एक गाँव से दूसरे गाँव में हस्तांतरण करने की सुविधा दी जाय |
   - VIII. एक पंचायत अंतर्गत SBM-G के IMIS में प्रविष्ट गाँवो की संख्या तथा वास्तविक गाँवो की संख्या में विभिन्नता को संशोधित करने की सुविधा प्रदान की जाय |
   - IX. SBM-G के IMIS की Speed को बढाया जाय |
   - X. SBM-G के IMIS में प्रविष्ट गलत पंचायत तथा गाँव के नामो को संशोधित करने की सुविधा दी जाय |
3. ओम प्रकाश अग्रवाल ने उपरोक्त बिन्दुओं पर Stepwise process पर चर्चा की और उसको करके प्रदर्शित किया (Stepwise process module are attached in Annex. Hence, please see PPT annex no.5,6&7) |
4. भारत सरकार के प्रतिनिधि श्री अग्रवाल द्वारा बताया गया कि सभी जिलें यथाशीघ्र डबल नाम वाले लाभार्थियों की जगह सही लाभार्थी की जानकारी प्रविष्ट करना सुनिश्चित करे अन्यथा भारत सरकार द्वारा डबल नाम वाले लाभार्थियों की जानकारी को IMIS से हटा दिया जायेगा (please see on http://sbm.gov.in Module B08)|
5. भारत सरकार के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि कार्यशाला के उपरांत भी यदि SBM-G के IMIS से सम्बंधित समस्या होने पर आप सभी राज्य स्तर पर डॉ अशोक कुमार को सूचित करे | डॉ अशोक कुमार भारत सरकार के संबंधित पदाधिकारी से संपर्क कर समस्या का समाधान प्राप्त करेंगे |

6. हर माह 15-15 दिनों के अन्तराल पर SBM-G के IMIS की प्रगति की समीक्षा विडियो कांफरेंशिंग (VC) के माध्यम से की जाएगी तथा IMIS से सम्बंधित समस्याओं का भी समाधान की जाएगी |

LSBA MIS

7. तकनीकी निदेशक – NIC पटना के द्वारा LSBA MIS की विस्तृत जानकारी दिया गया | तकनीकी निदेशक – NIC ने बताया कि Block Operator के login id से लाभार्थियों की जानकारी (Beneficiary ID Number) baseline survey (http://sbm.gov.in) से मिलाने के उपरांत entry किया जायेगा और Admin के login id से सत्यापन हेतु tagging तथा Advice generate किया जायेगा |
8. प्रतिभागियों के द्वारा बताया गया कि एक प्रखंड अंतर्गत कई लाभार्थियों का APL एवं BPL संख्या दोनों Same होने के स्थिति में लाभार्थियों की जानकारी MIS में entry नहीं हो पाती; जिसपर तकनीकी निदेशक के द्वारा बताया गया कि APL/BPL संख्या पंचायत code के साथ कर दिया जायेगा तो यह समस्या ख़त्म हो जाएगी |
9. कई जिलों में बैंक के द्वारा HTML file में advice माँगा जाता है जिसपर NIC के द्वारा बताया गया की इसका भी विकल्प MIS में कर दिया जायेगा |
10. प्रतिभागियों के द्वारा सुझाव दिया गया कि Final inspection के बाद एवं Advice generate के पहले entered data में सुधार हेतु एक विकल्प दिया जाय; जिसपर NIC के द्वारा बताया गया की इसका भी विकल्प MIS में कर दिया जायेगा |
11. कई जिलों से आग्रह किया गया कि प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु 12000/- के साथ 10000/- का भी दिया जाय ताकि पूर्व में SBM-G के MIS में दर्ज भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के साथ समायोजन किया जा सके |
12. मिशन निदेशक – लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRLPS ने बताया कि जीविका के द्वारा LSBA का क्रियान्वयन होने वाले प्रखंडो में 30 अगस्त से पूर्व का लंबित भुगतान जिला जल एवं स्वच्छता समिति के निर्णय के आधार पर किसी एक एजेंसी (जीविका या प्रखंड) के द्वारा किया जायेगा | उसके बाद का भुगतान सम्बंधित एजेंसी के द्वारा ही किया जायेगा |
13. मिशन निदेशक – लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान ने NIC को निदेशित किये कि गंगा कार्य योजना के तहत लाभार्थियों का भुगतान भी LSBA MIS के अंतर्गत होना है, इसलिए LSBA MIS में गंगा कार्य योजना के लाभार्थियों के भुगतान का विकल्प सृजित करना सुनिश्चित करे |
14. मिशन निदेशक – लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान ने जिलें यथा; पच्छिमी चंपारण, मुंगेर, समस्तीपुर, नवादा, नालंदा, मुजफ्फरपुर तथा सारण का भुगतान की प्रगति असंतोषजनक है, जिसपर मिशन निदेशक ने सम्बंधित जिला समन्वयक को निर्देश दिए कि प्रतिदिन भुगतान की समीक्षा करे और इसमें तेजी लाये |
15. मिशन निदेशक – लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान ने गंगा किनारे अवस्थित जिलें यथा; सारण, मुंगेर, पटना, समस्तीपुर, वैशाली, बक्सर, भागलपुर, खगड़िया, बेगुसराय, कटिहार, भोजपुर तथा लखीसराय में लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि तथा भुगतान की स्थिति असंतोषजनक है, जिसपर मिशन निदेशक ने सम्बंधित जिला समन्वयक को निर्देश दिए कि प्राथमिकता के आधार पर प्रतिदिन कार्यो की समीक्षा करे तथा निर्मित शौचालय के लाभार्थियों के खाते में भुगतान करवाना सुनिश्चित करे |
16. मिशन निदेशक - लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान ने NIC पटना को निदेश दिए कि शौचालय का Inspection हेतु Mobile App Base सुविधा को भी खोले, ताकि इसके तहत भी शौचालय का Inspection किया जाय |
17. प्रतिभागियों द्वारा सुझाव दिया गया कि किसी कारण से भुगतान नहीं होने पर सम्बंधित लाभार्थियों की जानकारी का विकल्प LSBA MIS में दिया जाय ताकि जिलों द्वारा अग्रतर कार्यवाही की जा सके |
18. प्रतिभागियों द्वारा सुझाव दिया गया कि Advice wise Report की सुविधा LSBA MIS में किया जाय |

04/7/16

(राजीव कुमार सिंह)
राज्य समन्वयक
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, बिहार

ज्ञापांक :- BRLPS/LSBA-ESH/08/16/043 दिनांक : 21.12.2016

प्रतिलिपिः सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति / सभी उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति / सभी निदेशक (लेखा)-सह-सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति/ सभी जिला समन्वयक, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/12/16

(राजीव कुमार सिंह)

राज्य समन्वयक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

Swachh Bharat Mission (G) – MIS

About SBM(G)

- Swachh Bharat Mission – Gramin (SBM-G) launched on 2nd Oct, 2014. The Objective of Swachh Bharat Mission (Gramin) is to make Rural India Open Defecation Free (ODF) by 2019 by construction of individual household toilets, cluster & community toilets. It also enhances to keep the villages clean through solid and liquid waste management.
- The online monitoring tool - http://sbm.gov.in , for this programme has been developed by NIC. The online monitoring system of SBM is a comprehensive web-based information system. The system enables the centre, state, district, block and panchayat to monitor the progress of construction of toilets for Individual household and community sanitary complexes.
- It also enables SMS communication with beneficiaries for ascertaining whether they are satisfied with toilets provided to them under the SBM-G programme.

Issues

- Villages are not showing while declaring ODF
- Reason:
  - Villages having zero households are not allowed to declare ODF. One module B7 is also developed and uploaded in MIS.
  - State will have to identify villages in four categories
    - Village not exists
    - Village exists but not habitated,
    - Village exists but data is not complete,
    - Village exists but data entered in other village)
- Shifting of data to other villages -
- Module is ready. It unloaded from website due to high memory utilisation and performance problem and data. We will open this module for limited period (Once in a year)
-
- Master Directory (Inclusion of newly GPs/ Villages) – Addition, deletion, renaming, shifting
- Reason: Module is already exists for directory updation. Addition/ deletion/ correction with be done by both water and sanitation team of state. Final correction has to be approved by both. Then we will reflect in our MIS.
- Urbanisation of Few Villages / Panchayats
- Addition of additional families behind Baseline data

- State CAP – On demand from states, CAP has been removed. We have given flexibility to state to decide district CAP whenever it is require. A module B05 has been developed and uploaded in MIS.
- Problem in photo uploading : Reasons:
- No network on mobile or in particular area
- Login Id & Password may be incorrect
- Wrong IMEI registered
- Web site is slow and taking long time
  - Reason:-
    - In existing infrastructure Concurrency of Users are too high i.e. on an average 7 K users are online during peak hours at IIS levels on each Application Server.
    - On Application servers CPU and Memory utilisation goes to 100%; due to this application performance get affected like (10% users are not getting proper response from the site/application/mob app)
- Large number of user population i.e. approx. 50K users are registered to use this portal using web and mobile interface while reported the IHHL toilet built along with IHHL toilet constructed photographs with their usages

SBM – MIS Components / Modules

- Additional / correction in baseline data of beneficiaries - (B01 & B02)
- Deletion of duplicate / multiple entries of same name – (B08)
- Shifting of families from one village to other - (B06)
- Updation / increase of district level CAP - (B05)
- Update the status of villages having zero households (Not exist/ Un-habitated / data in other village) - B07
- Declaration and Verification of villages - C20
- Tentative date of ODF declaration of districts -
- Progress reporting of toilets (physical and financial) - C01
- Approval process by districts / states - C02 & C03
- Extend of reporting of districts behind 9th of each month - C03

- Households accessing toilets of others (incase of ODF villages / districts to show 100% access) - C06
- Rating of villages (Village level Index) on Swachhta Index - C16
- Toilets constructed from Swachh Bharat Kosh and MNREGA etc. – C01
- Coverage of Dysfunctional toilets found in baseline survey - C08
- Households reported physical but financial entry pending / not complete - C13
- Deletion of unapproved progress – if entered wrongly' - C14

- Mapping of villages with Parliamentary / Assembly constituencies - D10
- Contact details of Gram Sarpanch - D05
- Contact details of District Collectors/ Magistrate - D05
- Contact details of district / Block MIS coordinators - D05
- Changes / reset of password of district level officers - D06

- Addresses of Grievances received from Citizens - D07
- Reporting of Solid & Liquid Expenditure - D02
- Reporting of IEC/HRD/ Admin Expenditure - D03
- Expenditure of other components - C05

- Release funds to district from state - A02
- Release funds to gram panchayats from district – if any - A08
- Community Incentive to panchayats – if any - A05
- SwachhApp – For Rating of villages by Citizens
- Viewing the status of villages on households reported
- MobileAPP - Uploading Photographs of toilets
  - Registration of mobile users for uploading photographs
  - Allocation of village / GP to mobile users
  - Approval / de-approve of photographs before showing on website
  - Delete/ update information of mobile users (Mobile , IMEI etc)

Key issues related to IMIS from Districts

- In many cases, all beneficiaries are listed against the name of GP. As there are no details of the village, habitation, so ,beneficiary search (for updating) is a tedious and time consuming task.
- New entry in beneficiary details is not possible.
- No details can be added in the Panchayats having no entry.
- Details with "Yes" toilet can't be updated .
- Removing duplicate names could not ensure adding beneficiary against each beneficiary removed .
- Making ODF of NGP Panchayats is real challenges, as having very minimal target
- BLS does not match with actual paid list .
- SECC data/detail is not considered in card details of beneficiary

Challenges

- No Intra Panchayat transfer/ shift of beneficiary, even after saturation of Panchayat is allowed .
- Some Districts entered more data than the approved number of beneficiary, that restricted other districts to enter actual data .
- Few Districts could not compete the entry of beneficiary details, as State figure reached to 2.13 Crore .
- Village wise figures not entered in IMIS, due to lack of understanding .
- Actual villages and habitations could not be found during the entry .
- Updating the exiting Beneficiary details is time consuming (8-10 mins/ update), as District having bandwidth limitation
- More than 25% NGP Panchayats have 80-100% coverage.